यू. पी.- पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024

सामान्य अध्ययन - I

प्रश्न-पत्र - V

खंड - अ

प्रश्न.1 न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की भूमिका का विश्लेषण करें।

उत्तर- उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने और विधि के शासन (Rule of Law) को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्य वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से करता है।

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में भूमिका:

- **कार्यकाल की सुरक्षा (Security of Tenure):**
  - अनुच्छेद 217 के तहत न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता, जिससे उनके निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष रहते हैं।
- **न्यायाधीशों की नियुक्ति:**
  - राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है (दूसरे और तीसरे न्यायाधीश मामलों के अनुसार)।
- **वित्तीय स्वतंत्रता:**
  - अनुच्छेद 221 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि (Consolidated Fund) से दिए जाते हैं, जिससे कार्यपालिका का हस्तक्षेप रोका जाता है।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:**
  - अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण देता है, जिससे आंतरिक अनुशासन और न्यायिक कार्य की स्वतंत्रता बनी रहती है।
- **बाहरी प्रभाव पर रोक:**
  - अनुच्छेद 220 न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद उसी न्यायालय में वकालत करने से रोकता है, जिससे किसी प्रकार का प्रभाव या पक्षपात न हो।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

- **शक्तियों का पृथक्करण:**
  - अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है, जो न्यायिक स्वतंत्रता का मूल आधार है।

विधि के शासन को बनाए रखने में भूमिका:

- **अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता:**
  - नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और राज्य के कार्यों की समीक्षा करके न्यायालय विधि के शासन को लागू करता है।
- **संवैधानिक वैधता का संरक्षक:**
  - राज्य सरकारों और प्रशासन को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाए रखने का कार्य करता है।
- **महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण:**
  - राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी (1975) मामले में, प्रधानमंत्री का निर्वाचन रद्द कर, उच्च न्यायालय ने न्यायिक साहस और निष्पक्षता का परिचय दिया।
- **अधीनस्थ न्यायपालिका की निगरानी:**
  - जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की नैतिकता और कार्य प्रणाली को नियंत्रित कर न्याय की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय अपने न्यायिक समीक्षा अधिकार, स्वायत्तता और ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाता है। यह न केवल न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता और नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करता है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.2 उत्तर प्रदेश में जाति-आधारित राजनीतिक दलों के उदय में योगदान देने वाले कारकों और राज्य के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करें।

उत्तर- भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, पिछले कुछ दशकों में जाति-आधारित राजनीतिक दलों के तीव्र उदय का साक्षी रहा है। इन दलों ने राज्य की सामाजिक-राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। इनके उदय के पीछे कई सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारक जिम्मेदार हैं, और इनकी भूमिका आज भी राज्य की राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण है।

जाति-आधारित दलों के उदय में योगदान देने वाले प्रमुख कारक:

- **ऐतिहासिक जातिगत पदानुक्रम:**
  - सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों को पारंपरिक रूप से सत्ता से बाहर रखा गया। इससे उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग उठाई।
- **मंडल राजनीति (1990 का दशक):**
  - मंडल आयोग की सिफारिशों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने से ओबीसी और दलित समुदायों का राजनीतिक रूप से उभार हुआ।
  - इसने समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसे दलों के लिए आधार तैयार किया।
- **करिश्माई नेतृत्व:**
  - मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे नेताओं ने जातिगत पहचान को संगठित कर सशक्त वोट बैंक तैयार किए और इसे सत्ता में बदलने में सफलता पाई।

राज्य के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव:

- **सत्ता समीकरणों में बदलाव:**
  - जाति-आधारित दलों के उदय से परंपरागत सवर्ण वर्चस्व वाली पार्टियों की सत्ता में पकड़ कमजोर पड़ी, जिससे राजनीतिक संतुलन बदला।
- **सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति:**
  - बसपा और सपा ने आरक्षण, शिक्षा, और रोजगार के माध्यम से दलितों और पिछड़ों के लिए सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) को बढ़ावा दिया।
- **राजनीतिक विखंडन और ध्रुवीकरण:**
  - जातिगत पहचान की राजनीति ने वोट बैंक की अवधारणाओं को बल दिया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ा।

जाति-आधारित राजनीतिक दलों का उदय उत्तर प्रदेश की राजनीति में सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व की एक नई धारा लेकर आया है। हालांकि इसने सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक विभाजन, वोट बैंक की राजनीति, और सामाजिक तनाव भी बढ़ा है। इन दलों की भूमिका ने राज्य की राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.3 भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आकार देने में उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व का परीक्षण करें।

उत्तर– उत्तर प्रदेश, भारत के सबसे ऐतिहासिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में से एक है, जिसने राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह क्षेत्र धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का पालना (cradle) रहा है, जिनका प्रभाव आज भी भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने में परिलक्षित होता है।

ऐतिहासिक महत्वः

1. प्रमुख धर्मों की जन्मस्थलीः

- **हिंदू धर्मः**
  - उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी, विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक है और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है।
  - रामायण और महाभारत की घटनाएं इस क्षेत्र से गहराई से जुड़ी हैं।
- **बौद्ध धर्मः**
  - यद्यपि बोधगया (बिहार) में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया।
  - इस क्षेत्र ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **जैन धर्मः**
  - काशी (वाराणसी) जैन धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ अनेक तीर्थंकरों का जन्म हुआ।

2. सांस्कृतिक एवं बौद्धिक केंद्रः

- उत्तर प्रदेश ने भारतीय दर्शन, साहित्य, और कला में अतुलनीय योगदान दिया है।
- संस्कृत साहित्य और भक्ति आंदोलन की रचनाएं, जैसे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, यहीं पनपीं।
- कथक नृत्य की परंपरा लखनऊ जैसे शहरों में समृद्ध हुई, जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊँचाइयाँ दीं।

3. राजनीतिक महत्वः

- यह क्षेत्र मौर्य, गुप्त, और बाद में मुगल साम्राज्य जैसी शक्तिशाली राजवंशों का केंद्र रहा।
- 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई, जिसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया।

4. वास्तुकला की विरासतः

- उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल (आगरा), प्रेम का प्रतीक और विश्व के नवीन सात अजूबों में से एक है।
- फतेहपुर सीकरी और शाहजहाँनाबाद जैसे स्थापत्य स्मारक मुगल वास्तुकला के प्रभाव को दर्शाते हैं।

उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक महत्व इस बात में निहित है कि यह भारत की धर्म, संस्कृति और राजनीति की भूमि रहा है।

यहाँ से जन्मे धार्मिक आंदोलन, साहित्यिक रचनाएं, संगीत एवं वास्तु विरासत न केवल भारतीय सभ्यता को आकार देते हैं, बल्कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान को भी दृढ़ करते हैं।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.4 उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव में वास्तुशिल्पीय महत्व और चुनौतियों का विश्लेषण करें।

उत्तर- उत्तर प्रदेश, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, और बड़ा इमामबाड़ा जैसे विश्वप्रसिद्ध स्मारक स्थित हैं। ये संरचनाएं हिंद-इस्लामी, मुगल, और स्थानीय वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं।

स्थापत्य महत्वः

- **सांस्कृतिक समन्वयः**
  - उत्तर प्रदेश के स्मारकों में हिंदू, इस्लामी और बौद्ध वास्तुशैली का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, जैसे कि सारनाथ स्तूप और काशी विश्वनाथ मंदिर में।
- **प्रतीकात्मकता और वैश्विक आकर्षणः**
  - ताजमहल, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इसकी संतुलित संरचना, उत्कृष्ट नक्काशी और संगमरमर कार्य विश्व प्रसिद्ध हैं।
- **आर्थिक मूल्यः**
  - आगरा और वाराणसी जैसे शहरों में विरासत पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी प्रोत्साहन मिलता है, जिससे रोजगार और व्यवसाय में वृद्धि होती है।

संरक्षण में चुनौतियाँः

- **प्रदूषणः**
  - वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और सूक्ष्म कणों के कारण, ताजमहल के संगमरमर का रंग फीका पड़ रहा है।
- **शहरी अतिक्रमणः**
  - ऐतिहासिक स्थलों के आस-पास भीड़भाड़ और अवैध निर्माण उनके परिसर की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
- **कुशल जनशक्ति की कमीः**
  - संरक्षण विशेषज्ञों की कमी, और वित्तीय संसाधनों की अनियमितता के कारण पुनर्स्थापन कार्यों में देरी होती है।
- **जलवायु प्रभावः**
  - नमी में वृद्धि और अम्लीय वर्षा (Acid Rain) जैसे मौसम संबंधी परिवर्तन भी संरचनाओं को क्षति पहुँचा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की विरासत संरचनाओं के सतत संरक्षण के लिए एक समन्वित रणनीति आवश्यक है, जिसमें तकनीक, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, और मजबूत कानूनी व्यवस्था को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

केवल संरक्षण नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सतत प्रयासों के माध्यम से ही इन स्थापत्य धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.5 उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध और ऑनलाइन कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में बाहरी और अंतरराज्यीय कारकों की भूमिका पर चर्चा करें।

उत्तर- उत्तर प्रदेश, जहाँ युवाओं की बड़ी आबादी है और डिजिटल पहुंच तेजी से बढ़ रही है (TRAI 2023 के अनुसार 9.3 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपभोक्ता), साइबर अपराध और ऑनलाइन उग्रवाद के लिए बाहरी और अंतर-राज्यीय तत्वों का प्रमुख निशाना बनता जा रहा है।

बाहरी कारकों की भूमिका:

- **सीमापार उग्रवाद:** पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा एन्क्रिप्टेड ऐप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करते हैं।
- **फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स:** उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा कई भड़काऊ पोस्ट को पाकिस्तान और खाड़ी देशों के आईपी एड्रैस से जोड़ा गया है।
- **डिजिटल हवाला और क्रिप्टोकरेंसी:** विदेश स्थित संचालक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स के माध्यम से स्लीपर सेल्स को फंडिंग और गलत सूचना फैलाने के अभियान को समर्थन प्रदान करते हैं।

अंतर-राज्यीय कारकों की भूमिका:

- **साइबर अपराध केंद्र:** झारखंड के जामताड़ा और हरियाणा के मेवात जैसे क्षेत्र फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सेक्सटॉर्शन के लिए कुख्यात हैं, जिनके शिकार उत्तर प्रदेश के नागरिक बनते हैं।
- **सांप्रदायिक तनाव:** अन्य राज्यों से उत्पन्न फर्जी वीडियो और घृणास्पद कंटेंट ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। उदाहरण: 2013 मुजफ्फरनगर दंगे से पहले वायरल हुए भ्रामक वीडियो।
- **नौकरी और सेक्सटॉर्शन घोटाले:** फर्जी नौकरी प्रस्ताव और हनीट्रैप जैसे मामलों में अक्सर पश्चिम बंगाल और दिल्ली से संचालित साइबर गिरोहों का हाथ पाया गया है।

इन सीमापार और अंतर-राज्यीय डिजिटल खतरों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को चाहिए कि वह मजबूत अंतर-राज्यीय खुफिया नेटवर्क स्थापित करे, संपर्क और समन्वय आधारित साइबर पुलिसिंग (जैसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र - I4C) को बढ़ावा दे, डिजिटल साक्षरता का प्रसार करे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणालियों को अपनाए।

केवल तकनीकी उपाय ही नहीं, बल्कि नीतिगत और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से भी इन खतरों को रोका जा सकता है।

प्रश्न.6 किसी राज्य की विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका का मूल्यांकन करें।

उत्तर- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना गया है। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और केंद्र व राज्य के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका औपचारिक होने के साथ-साथ कुछ स्थितियों में विवेकाधीन भी होती है।

विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका:

1. विधानमंडल को बुलाना और भंग करना (अनुच्छेद 174):

- राज्यपाल विधानसभा को आह्वान, स्थगन और भंग कर सकते हैं।
- यह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है, किंतु राजनीतिक टकराव की स्थितियों में देरी विवाद का कारण बनती है।

2. विधानमंडल को संबोधित करना (अनुच्छेद 176):

- राज्यपाल हर वर्ष के पहले सत्र में सदन को संबोधित करते हैं और सरकार की नीतियों व प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करते हैं।

3. विधेयकों को स्वीकृति देना (अनुच्छेद 200):

- राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं:
  - a) स्वीकृति देना
  - b) अस्वीकृति देना
  - c) पुनर्विचार हेतु लौटाना (धन विधेयकों को छोड़कर)
  - d) राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना
- हाल के वर्षों में, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा अनावश्यक विलंब पर सवाल उठे हैं।

4. अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद 213):

- जब विधानसभा सत्र में न हो, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी वैधता एक विधेयक के समान होती है।
- परंतु लगातार अध्यादेशों का प्रयोग विधायी प्रक्रिया को कमजोर करता है और इसकी आलोचना होती रही है।

हालांकि राज्यपाल की भूमिका सामान्यत: औपचारिक होती है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता या संवैधानिक संकट की स्थिति में यह भूमिका निर्णायक बन जाती है। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने और उनके कार्यों को संविधान की भावना व संघीय ढांचे के अनुरूप बनाए रखने की सिफारिश की है।

इसलिए, राज्यपाल की भूमिका को पारदर्शी, गैर-पक्षपातपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाए रखने के लिए सुधारों और स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।

प्रश्न.7 उत्तर प्रदेश के शासन पर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभाव पर चर्चा करें।

उत्तर- केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) ऐसे प्रमुख उपकरण हैं जिनके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करती है। उत्तर प्रदेश (UP) जैसे विशाल और जनसंख्या-सघन राज्य में इन योजनाओं ने शासन की गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभाई है।

उत्तर प्रदेश पर सकारात्मक प्रभावः

1. सेवाओं की गुणवत्ता में सुधारः

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):** 90% से अधिक गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया।
- **आयुष्मान भारत योजनाः** 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिली।

2. लक्षित कल्याण और समावेशनः

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):** वंचित वर्गों को 30 लाख से अधिक घर आवंटित।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM):** विशेषकर पूर्वांचल में महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया।

3. डिजिटल और ई-गवर्नेंस को बढ़ावाः

- **भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण (DILRMP):** भूमि विवादों में कमी और पारदर्शिता में वृद्धि।

4. शैक्षिक व पोषण संबंधी सुधारः

- **समग्र शिक्षा योजना और मिड-डे मीलः** पिछड़े जिलों में नामांकन और छात्र उपस्थिति में सुधार।

चुनौतियाँ और सीमाएँः

- **एकरूप दृष्टिकोणः** स्थान विशेष की जरूरतों की उपेक्षा होती है।
- **वित्तीय देरी और कार्यान्वयन क्षमता की कमीः** स्थानीय स्तर पर प्रभावशीलता घटती है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप और विभागीय समन्वय की कमीः** योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाता है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने उत्तर प्रदेश में शासन क्षमता को मजबूत किया है, लेकिन इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित, समन्वित और पारदर्शी ढंग से लागू करे। संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना और स्थानीय योजना निर्माण को बढ़ावा देना, सतत और समावेशी विकास की कुंजी है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.8 उत्तर प्रदेश में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए स्मार्ट सिटी और अमृत योजनाओं के प्रभाव पर चर्चा करें।

उत्तर- उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, कानपुर जैसे तीव्र गति से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से यातायात जाम, प्रदूषण, और अव्यवस्थित नागरिक सेवाओं की समस्या रही है। ऐसे में स्मार्ट सिटी मिशन और अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) ने शहरी शासन और अवसंरचना सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्मार्ट सिटी मिशन का प्रभावः

- **शहर-विशिष्ट समाधानः** वाराणसी, आगरा, और कानपुर में स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, LED स्ट्रीट लाइटिंग, और स्मार्ट निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकें लागू की गई।
- **ई-गवर्नेंस का विस्तारः** नागरिक सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप, शिकायत निवारण तंत्र, और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली से पारदर्शिता व भागीदारी बढ़ी।
- **सार्वजनिक अवसंरचना में सुधारः** स्मार्ट क्लासरूम, सड़कों का पुनर्विकास, नदी तट सौंदर्यीकरण, और सौर ऊर्जा संयंत्रों ने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर किया।

अमृत योजना का प्रभावः

- **जल आपूर्ति और सीवरेज सुधारः** 80 से अधिक नगरीय निकायों (ULBs) में पाइप जल आपूर्ति और मलजल शोधन संयंत्रों में सुधार।
- **हरित क्षेत्रों का विकासः** अलीगढ़ और मुरादाबाद जैसे शहरों में नवीन शहरी पार्क विकसित कर पर्यावरण संतुलन में योगदान।
- **प्रशासनिक क्षमता में वृद्धिः** शहरी निकायों को प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी से सक्षम बनाया गया है।

प्रमुख चुनौतियाँः

- **कार्यान्वयन में देरीः** भूमि अधिग्रहण व ठेकेदार संबंधी बाधाओं के कारण कई परियोजनाएं विलंबित हैं।
- **असमानताः** छोटे शहरों में प्रशासनिक क्षमता की कमी के कारण सेवाओं की गुणवत्ता में अंतर बना हुआ है।

स्मार्ट सिटी और अमृत योजना ने उत्तर प्रदेश में शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में ठोस प्रगति की है। **परंतु इन योजनाओं की स्थायित्वपूर्ण सफलता के लिए आवश्यक है - समयबद्ध क्रियान्वयन, स्थानीय निकायों की क्षमता वृद्धि, और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी।**

सामूहिक प्रयासों से ही उत्तर प्रदेश की शहरी संरचना को टिकाऊ और समावेशी बनाया जा सकता है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.9 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तरप्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का मूल्यांकन करें।

उत्तर- जिसे अक्सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का उद्गम स्थल कहा जाता है, ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस राज्य ने कई प्रमुख नेताओं को जन्म दिया जिनके योगदान ने आंदोलन के उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारी दोनों चरणों को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमुख योगदानः

1. मंगल पांडे – विद्रोह की पहली चिंगारी

- बैरकपुर में उनका विद्रोह (1857) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्प्रेरक बन गया।
- बलिया जिले से आने वाले वे ब्रिटिश दमन के विरुद्ध प्रारंभिक प्रतिरोध के प्रतीक थे।

2. मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू – वैचारिक और राजनीतिक नेतृत्व

- मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की सह-स्थापना की और लाहौर अधिवेशन (1928) की अध्यक्षता की।
- जवाहरलाल नेहरू सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे, और बाद में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।

3. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई – साहस की प्रतीक

- ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह में उनका नेतृत्व स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी का एक प्रतिष्ठित उदाहरण बना हुआ है।

4. चन्द्रशेखर आजाद – क्रांतिकारी राष्ट्रवादी

- उन्नाव जिले के आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) के प्रमुख सदस्य थे और काकोरी षड्यंत्र (1925) में शामिल थे।

5. पुरूषोत्तम दास टंडन और गोविंद बल्लभ पंत

- उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने की वकालत की और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों ने न केवल जनता को संगठित किया, बल्कि बलिदान, विचारधारा और नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्रवादी चेतना को भी प्रेरित किया। उनकी विरासत भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक लोकाचार को आकार दे रही है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.10 ग्रामीण उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना को आकार देने में त्योहारों, मेलों और लोक परंपराओं की भूमिका का वर्णन करें।

उत्तर- ग्रामीण उत्तर प्रदेश में त्यौहार, मेले और लोक परंपराएँ क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने और सामुदायिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक प्रासंगिकता बहुत गहरी है।

ग्रामीण उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना को आकार देने में त्योहारों, मेलों और लोक परंपराओं की भूमिका

1. सांस्कृतिक एकीकरण और सामुदायिक बंधन

- होली, दिवाली और ईद जैसे त्यौहार विभिन्न धार्मिक और जातीय पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ आने का अवसर प्रदान करते हैं।
- ये उत्सव पारंपरिक सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठकर एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं।

2. सामाजिक पदानुक्रम और जातिगत गतिशीलता

- धार्मिक त्यौहार और मेले (जैसे, प्रयागराज में माघ मेला) इस क्षेत्र की जाति-आधारित संरचना को उजागर करते हैं, जहां भूमिकाएं और भागीदारी अक्सर जाति से प्रभावित होती हैं।
- कुंभ मेला, सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जो पारंपरिक शक्ति गतिशीलता को दर्शाता है, जिसमें विशिष्ट जाति समूह तीर्थयात्राओं और अनुष्ठानों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

3. आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता

- सोनपुर मेला (जो उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रिय है) जैसे मेले व्यापारियों और हाशिए पर पड़े समूहों को वाणिज्य में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
- ये आयोजन आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं और सामाजिक संपर्क के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं, आर्थिक गतिशीलता में योगदान देते हैं और सामाजिक बाधाओं को तोड़ते हैं।

4. विरासत का संरक्षण

- रामलीला प्रदर्शन, ढोलक संगीत और कथक नृत्य जैसी लोक परंपराएं सांस्कृतिक कहानियों और मूल्यों को आगे बढ़ाती हैं।
- ये परंपराएं ग्रामीण उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करती हैं, साथ ही पीढ़ियों के बीच सामाजिक मानदंडों को सुदृढ़ बनाती हैं।

5. सामुदायिक विकास में भूमिका

- धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव सामुदायिक विकास के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं, जहां ग्रामीण निवासी सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों की योजना बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करते हैं, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं।

6. स्थानीय पहचान का निर्माण

- काशी विश्वनाथ मेला और बाराबंकी जैसे क्षेत्रीय मेले बारहमासा मेला साझा परंपराओं और सांप्रदायिक भागीदारी के आधार पर स्थानीय पहचान बनाता है।

संक्षेप में, त्यौहार, मेले और लोक परंपराएं ग्रामीण उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना को महत्वपूर्ण रूप से आकार देती हैं, तथा आर्थिक गतिविधियों, सामुदायिक एकजुटता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को प्रभावित करती हैं।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

खंड - ब

प्रश्न.11 उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना और मिशन शक्ति के प्रभाव का विश्लेषण करें।

उत्तर- एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना और मिशन शक्ति ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, स्थानीय उद्योगों, रोजगार सृजन और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना का प्रभाव

1. **स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना :** ओडीओपी योजना में उत्तर प्रदेश के 75 उत्पादों को शामिल किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अपने जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरणों में शामिल हैं:
   - **आगरा :** पेठा (एक पारंपरिक मिठाई) के लिए प्रसिद्ध।
   - **वाराणसी :** बनारसी रेशम और कपड़ों के लिए प्रसिद्ध।
   - **कन्नौज :** इत्र (पारंपरिक इत्र) के लिए जाना जाता है।
   - **मुरादाबाद :** पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध।
2. **आर्थिक विकास और रोजगार सृजन :** राज्य में 2 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं, खासकर कारीगरों और लघु-स्तरीय निर्माताओं के लिए। इस योजना ने एमएसएमई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपस्थिति को बढ़ावा दिया है और आत्मनिर्भर व्यवसाय बनाने में मदद की है।
3. **निर्यात को बढ़ावा :** बनारसी रेशम, पेठा और मुरादाबाद पीतल के बर्तन जैसे ओडीओपी उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच गए हैं, जिससे राज्य की निर्यात क्षमता बढ़ गई है।
4. **बुनियादी ढांचे का विकास :** इस योजना से बुनियादी ढांचे में सुधार, विशेष रूप से पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स में 3,200 करोड़ रुपये के निवेश की सुविधा मिली है।

उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का प्रभाव

1. **महिला सशक्तिकरण :** 1.4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) स्थापित किए गए हैं, जिससे 25 लाख महिलाओं को लाभ मिला है। महिलाएं अब उद्यमिता और नेतृत्व की भूमिकाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।
2. **वित्तीय समावेशन :** 10,000 करोड़ रुपये के वित्त पोषण से महिलाओं के सूक्ष्म उद्यमों और आजीविका को समर्थन मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

3. **सामाजिक जागरूकता और सुरक्षा :** मिशन शक्ति के अभियान 2 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुँच चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ी है।

ओडीओपी योजना और मिशन शक्ति दोनों ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे राज्य के लोगों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है।

1.50 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 1.83 करोड़ निःशुल्क LPG कनेक्शन	स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.75 करोड़ टॉयलेट (इज्जत घर का निर्माण)	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 60 लाख से अधिक माताएं लाभान्वित
PM स्वामित्व योजना के तहत 66 लाख से अधिक स्वामित्व सर्टिफिकेट का वितरण	PM स्वनिधि योजना के तहत 2 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ	PM आवास योजना के तहत 56 लाख घरों का निर्माण	बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के तहत 1.9 करोड़ से अधिक बलिकाओं का सशक्तीकरण
SHG के 2.35 लाख सदस्यों को 2352 करोड़ का ऋण वितरण	मिशन शक्ति के तहत 8.99 करोड़ महिलाओं का सशक्तीकरण	शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 4500 पिंक टॉयलेट का निर्माण	स्नातक स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.12 स्थानीय निकाय चुनाव कराने में उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका की व्याख्या करें।

उत्तर- उत्तर प्रदेश का राज्य चुनाव आयोग (SEC) राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी स्थानीय निकाय चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य है। यहाँ इसकी भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया है:

1. संवैधानिक और कानूनी अधिदेश

- एसईसी एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 243के (पंचायतों के लिए) और अनुच्छेद 243जेडए (नगर पालिकाओं के लिए) के तहत की गई है।
- यह उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 आदि द्वारा शासित है।

2. चुनाव का संचालन

- निम्नलिखित के लिए चुनावों का **अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण :**
  - ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें।
  - नगर पंचायतें, नगर पालिका परिषदें और नगर निगम।
- चुनाव कार्यक्रमों को अंतिम रूप देना, अधिसूचना जारी करना और आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन की देखरेख करना।

3. परिसीमन और आरक्षण

- स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के परिसीमन का पर्यवेक्षण या सहायता करना।
- संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

4. मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन

- स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी, अद्यतनीकरण और रखरखाव का पर्यवेक्षण करना।
- यह सुनिश्चित करता है कि डुप्लिकेट मतदाताओं को हटाया जाए, पात्र मतदाताओं को शामिल किया जाए तथा आपत्तियों का निपटारा किया जाए।

5. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना

- मतदान कार्मिकों की तैनाती, प्रशिक्षण आयोजित करना और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- व्यय सीमा, अभियान उल्लंघनों और चुनावी कदाचारों पर नजर रखता है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

6. न्यायनिर्णयन और विवाद समाधान

- अयोग्यता, चुनाव याचिकाओं और उल्लंघनों के मुद्दों सहित चुनाव विवादों पर निर्णय लेना।

❖ अनियमितताओं या शांति के लिए खतरे की स्थिति में चुनाव रद्द करने या स्थगित करने की शक्ति रखता है।

7. मतदाता जागरूकता और भागीदारी

- मतदाता शिक्षा अभियान (जैसे राज्य स्तर पर SVEEP) आयोजित करना।
- यह विशेष रूप से युवाओं और हाशिए पर पड़े समूहों के बीच अधिकाधिक चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देता है।

8. प्रौद्योगिकी का उपयोग

- पैमाने के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) या मतपत्रों का क्रियान्वयन।
- मतदान निगरानी, परिणाम सारणीकरण और सूचना के सार्वजनिक प्रसार के लिए आईटी उपकरणों का उपयोग करता है।

उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ वैधता और जवाबदेही के साथ काम करें। यह गाँव और शहर के स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा करता है, जिससे संविधान द्वारा परिकल्पित विकेंद्रीकरण को और मजबूती मिलती है।

प्रश्न.13 उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा वितरण पर डिजिटल शासन पहल के प्रभाव का परीक्षण करें।

उत्तर- डिजिटल गवर्नेंस से तात्पर्य सरकारी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने तथा पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से है।

लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में डिजिटल पहलों ने आवश्यक सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच में सुधार, भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है।

1. पोर्टल और ऐप्स के माध्यम से उन्नत सेवा वितरण

- **ई-साथी पोर्टल :** जन्म, आय और जाति प्रमाण-पत्र सहित 200 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है, जिससे भौतिक यात्राओं और बिचौलियों की आवश्यकता कम हो जाती है।
- **सेवा मित्र ऐप :** यह ऐप नागरिकों को प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन जैसे सत्यापित सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है, जिससे सेवा तक पहुंच आसान हो जाती है।

2. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

- **भूलेख यूपी :** डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है।
- **प्रभाव :** भूमि विवादों में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि, तथा भूमि को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके ऋण तक आसान पहुंच।

3. कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)

- पीएम-किसान, कन्या सुमंगला योजना और मनरेगा मजदूरी सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जाती है।
- इससे भुगतान में होने वाली अनियमितताएं कम होंगी, समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को सशक्त बनाया जाएगा।

4. बेहतर शिकायत निवारण तंत्र

- **सीएम हेल्पलाइन 1076 :** नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने और उनके समाधान पर नजर रखने के लिए एक केंद्रीकृत मंच।
- **एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस-यूपी) :** विभागीय प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है और नौकरशाही जवाबदेही बढ़ाती है।

5. सार्वजनिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया गया

- **यूपी 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली :** पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवाओं को एकीकृत करती है, जिससे त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है।
- **शहरों में एआई-आधारित निगरानी :** इससे कानून प्रवर्तन में वृद्धि होगी, विशेष रूप से लखनऊ और नोएडा जैसे शहरी केंद्रों में।

6. डिजिटल शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना

- **डिजी शक्ति पोर्टल :** डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए 20 लाख से अधिक छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए।
- **स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एसएमआईएस) :** सरकारी स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति और प्रदर्शन पर नजर रखती है।

7. स्वास्थ्य सेवा और टेलीमेडिसिन सेवाएं

- **ई-संजीवनी ओपीडी :** ग्रामीण मरीजों को टेली-परामर्श प्रदान करती है, जिससे यात्रा की आवश्यकता कम हो जाती है।
- **डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड :** रोगी के इतिहास पर नजर रखने और कुशल देखभाल को सक्षम करने के लिए आयुष्मान भारत के तहत सुविधा प्रदान की गई।

डिजिटल गवर्नेंस ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा वितरण की पहुंच, गुणवत्ता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया है। हालांकि इन पहलों ने लंबे समय से चली आ रही शासन चुनौतियों का समाधान किया है, लेकिन डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करना, मजबूत डेटा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास इन लाभों को बनाए रखने और गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

प्रश्न.14 उत्तर प्रदेश में चरमपंथी गतिविधियों से निपटने में कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

उत्तर- भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश (यूपी) अपनी रणनीतिक स्थिति और सामाजिक-राजनीतिक जटिलताओं के कारण चरमपंथी खतरों के प्रति संवेदनशील रहा है।

कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने इन खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।

1. सक्रिय निगरानी और खुफिया ऑपरेशन

- **आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस):** यूपी एटीएस ने भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस), जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) और हाल ही में आईएसआईएस से प्रेरित स्थानीय कोशिकाओं जैसे आतंकवादी संगठनों के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 2021 में यूपी एटीएस ने लखनऊ से दो संदिग्ध एक्यूआईएस गुर्गों को गिरफ्तार किया, जो सार्वजनिक स्थानों पर हमले की योजना बना रहे थे।
- खतरों को रोकने में सक्रिय रहते हुए भी, खुफिया एजेंसियां अक्सर एनआईए और आईबी से प्राप्त केंद्रीय इनपुट पर निर्भर रहती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर स्वतंत्र खुफिया क्षमताओं की कमी उजागर होती है।

2. कट्टरपंथ विरोधी उपाय

- **सामुदायिक पुलिसिंग :** कट्टरपंथ की शीघ्र पहचान के लिए धार्मिक नेताओं और स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित करने की पहल की गई है।
- **मदरसा निगरानी और कट्टरपंथ-विरोधी कार्यशालाएं :** संदिग्ध धार्मिक संस्थानों की लक्षित निगरानी और जागरूकता अभियानों के माध्यम से क्षमता निर्माण।
- **इन उपायों के कारण प्रायः** प्रोफाइलिंग और भेदभाव के आरोप लगते हैं, विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं के विरुद्ध, जिससे अविश्वास और सामाजिक अलगाव पैदा होता है।

3. केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय

- **एनआईए, आईबी के साथ संयुक्त अभियान :** यूपी पुलिस और एटीएस अक्सर सीमा पार आतंकवाद और साइबर कट्टरपंथ की जांच के लिए राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करते हैं।
- 2022 में एक समन्वित अभियान के तहत पाकिस्तान समर्थित मॉड्यूल से जुड़े कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।
- उच्च-स्तरीय मामलों में प्रभावी, लेकिन प्रायः प्रतिक्रियाशील प्रकृति का।
- समन्वय में देरी और अधिकार क्षेत्र के ओवरलैप के कारण कभी-कभी जांच में बाधा उत्पन्न होती है।

4. साइबर निगरानी को मजबूत करना

- **साइबर अपराध इकाइयाँ :** विशेष इकाइयाँ ऑनलाइन चरमपंथी सामग्री की निगरानी करती हैं, जिसमें डार्क वेब फोरम और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आईएसआईएस से प्रेरित प्रचार प्रसार के मामलों में गिरफ्तारियां की गईं।
- कानून प्रवर्तन के निचले स्तरों में सीमित डिजिटल फोरेंसिक क्षमता और कुशल जनशक्ति, प्रारंभिक हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को कम करती है।

5. राजनीतिक और सांप्रदायिक आयाम

- **एनएसए और यूएपीए का उपयोग :** राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम का उपयोग सांप्रदायिक उकसावे या कट्टरपंथी गतिविधि के संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए किया गया है।
- शीघ्र सुनवाई के बिना कड़े कानूनों का अति प्रयोग या दुरुपयोग, मानवाधिकारों के उल्लंघन और चयनात्मक प्रवर्तन की चिंताएं उत्पन्न करता है।
- नागरिक अधिकार संगठनों ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की अत्यधिक कार्रवाई के लिए गिरफ्तारियों की आलोचना की थी।

6. कानून प्रवर्तन सुधार और प्रशिक्षण

- **क्षमता निर्माण :** आतंकवाद-रोधी रणनीति, निगरानी तकनीक और सांप्रदायिक संवेदनशीलता पर पुलिस अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण।
- उत्तर प्रदेश पुलिस ने संवेदनशील जिलों में चेहरे की पहचान प्रणाली और एआई-सक्षम निगरानी का उपयोग शुरू कर दिया है।
- निचली न्यायपालिका और अभियोजन पक्ष अक्सर साक्ष्यों के खराब प्रबंधन या प्रक्रियागत खामियों के कारण गिरफ्तारियों को दोषसिद्धि में बदलने में पिछड़ जाते हैं।

जबकि यूपी की एजेंसियों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, उनके कामकाज को जवाबदेही और कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। राज्य में चरमपंथ का स्थायी रूप से मुकाबला करने के लिए तकनीकी क्षमता, जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी और सामुदायिक विश्वास को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.15 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की भूमिका पर चर्चा करें, 1857 के विद्रोह और उसके बाद के दौरान इसके योगदान पर प्रकाश डालें।

उत्तर- उत्तर प्रदेश (तब संयुक्त प्रांत का हिस्सा) ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। राष्ट्रवादी चेतना के उद्‌गम स्थल के रूप में, इस क्षेत्र ने 1857 के विद्रोह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रतिष्ठित नेताओं और जन-आंदोलनों को देखा है।

1857 के विद्रोह के दौरान भूमिका

1. विद्रोह का केंद्र

- 1857 का विद्रोह उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुरू हुआ, जब सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया।
- दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और फतेहपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र बन गए।
- झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध उग्र प्रतिरोध का नेतृत्व किया।
- अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह का समन्वय किया।

1857 के बाद की भूमिका

1. राष्ट्रवादी आंदोलनों का घर

- लखनऊ (1916) और इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों ने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया।
- असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में उत्तर प्रदेश के जिलों से बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई।

2. नेताओं का योगदान

- इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के संवैधानिक और राजनीतिक आंदोलनों के केंद्र में थे।
- चौधरी चरण सिंह और पुरुषोत्तम दास टंडन भी प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभरे।

3. क्रांतिकारी गतिविधियाँ

- बनारस और फैजाबाद जैसे शहर अनुशीलन समिति और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) से जुड़ी क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र थे।

उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार, सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि ने इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक जीवंत मंच बनाया। 1857 से 1947 तक, इसने ऐसे नेताओं, विचारों और आंदोलनों का योगदान दिया, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के मार्ग को निर्णायक रूप से आकार दिया।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.16 समावेशी विकास के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण उत्तर प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण करें।

उत्तर- ग्रामीण उत्तर प्रदेश (यूपी), जहां राज्य की 70% से अधिक आबादी रहती है, गरीबी, कम साक्षरता, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य संकेतकों जैसी गहरी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।

ये मुद्दे समावेशी विकास में बाधा डालते हैं और क्षेत्रीय असमानताओं में योगदान देते हैं।

प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ

1. गरीबी और बेरोजगारी

- ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा हिस्सा कम उपज वाली कृषि या आकस्मिक मजदूरी पर निर्भर है।
- नीति आयोग के 2023 बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्यों में शुमार है।

2. कम कृषि उत्पादकता

- खंडित भूमि जोत, अपर्याप्त सिंचाई और कम मशीनीकरण कृषि आय को प्रभावित करते हैं।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र बार-बार आने वाली बाढ़ और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण विशेष रूप से संवेदनशील है।

3. स्वास्थ्य और शिक्षा के खराब परिणाम

- उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, कम संस्थागत प्रसव और कुपोषण कायम है।
- लिंग संबंधी मानदंडों और खराब स्वच्छता के कारण लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर अभी भी ऊंची बनी हुई है।

4. जाति और लिंग आधारित असमानताएँ

- अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों को भूमि, ऋण और सेवाओं तक पहुंच पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है।
- भारत में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है।

समावेशी विकास के लिए समाधान

1. कृषि सुधार

- फसल विविधीकरण, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण उत्तर प्रदेश में पीएम-कुसुम और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज का विस्तार किया जाना चाहिए।

2. मानव पूंजी निवेश

- आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डिजिटल शिक्षा उपकरणों का विस्तार करना।
- ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम आवश्यक हैं।

3. लक्षित सामाजिक योजनाएँ

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के अंतर्गत मनरेगा और ग्रामीण आवास के कार्यान्वयन को मजबूत करना।
- गरीबों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)।

4. स्थानीय शासन के माध्यम से सशक्तीकरण

- ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाना, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए।

ग्रामीण उत्तर प्रदेश की चुनौतियां जटिल हैं, लेकिन कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समानता में सतत निवेश के माध्यम से इनका समाधान किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकास के मार्ग में कोई भी पीछे न छूटे।

Chronicle ias

प्रश्न.17 अवैध प्रवास, मानव तस्करी और तस्करी (Smuggling) के उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें। इन मुद्दों के समाधान के लिए समाधान सुझाएँ।

उत्तर- उत्तर प्रदेश (यूपी) अपनी विशाल सीमाओं, जनसंख्या घनत्व और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं (विशेष रूप से नेपाल) से निकटता के कारण अवैध प्रवास, मानव तस्करी और तस्करी की चपेट में तेजी से आ रहा है।

इन गतिविधियों से न केवल आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है।

आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव

1. अवैध प्रवास और जनसांख्यिकीय तनाव

- नेपाल और बांग्लादेश से आने वाले लोगों के कारण स्थानीय जनसांख्यिकी में परिवर्तन होता है, जिससे प्रायः जातीय तनाव पैदा होता है और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव पड़ता है।
- महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर जैसे सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों ने अवैध बस्तियों के बढ़ने की सूचना दी है।

2. मानव तस्करी में वृद्धि

- महिलाओं और बच्चों, विशेषकर गरीब या दलित समुदायों से, बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण और घरेलू काम के लिए तस्करी की जाती है।
- उत्तर प्रदेश एक स्रोत और पारगमन राज्य दोनों है; एनसीआरबी 2022 के आंकड़ों से 400 से अधिक तस्करी के मामले सामने आते हैं, जिनमें से कई अंतर-राज्यीय और सीमा पार सिंडिकेट से जुड़े हैं।

3. माल और नशीले पदार्थों की तस्करी

- हथियारों, सोने, जाली मुद्रा और नशीले पदार्थों की तस्करी कानून और व्यवस्था के लिए खतरा बन गई है।
- बहराइच और लखीमपुर खीरी जैसे भारत-नेपाल सीमावर्ती जिले सीमा पार तस्करी के लिए कुख्यात हैं, जो अक्सर संगठित अपराध से जुड़े होते हैं।

सुझाए गए समाधान

1. सीमा निगरानी को मजबूत करना

- छिद्रयुक्त सीमाओं पर उन्नत निगरानी तकनीक और ड्रोन तैनात करें।
- सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाना ।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

2. अंतर–राज्यीय और अंतर–एजेंसी समन्वय

- यूपी एटीएस या एसटीएफ के तहत तस्करी और मानव तस्करी के मामलों के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया जाए।

3. सामुदायिक जागरूकता और पुनर्वास

- उज्ज्वला और वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान और पीड़ितों का पुनर्वास।

4. कानूनी और संस्थागत सुधार

- मानव तस्करी के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी; जिला स्तर पर मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा।

इन सुरक्षा चुनौतियों पर अंकुश लगाने और उत्तर प्रदेश में कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए बहुआयामी, समन्वित और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.18 उत्तर प्रदेश के सामने साइबर सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? राज्य स्तर पर साइबर लचीलेपन को मजबूत करने के लिए रणनीति सुझाएँ।

उत्तर- जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश (यूपी) शासन, वित्त और शिक्षा में अपने डिजिटल परिवर्तन को तेज कर रहा है, उसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

अपनी विशाल जनसंख्या और बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढांचे के कारण राज्य साइबर खतरों के प्रति तेजी से संवेदनशील हो गया है।

प्रमुख साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ

1. साइबर अपराधों में वृद्धि

- फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, रैनसमवेयर और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं।
- एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 71% रैनसमवेयर हमले उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट किए गए (10,117 साइबर अपराध)

2. ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर साइबर बुनियादी ढांचा

- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल निरक्षरता और सुरक्षित प्रणालियों की कमी के कारण वे धोखेबाजों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं।

3. डेटा गोपनीयता चिंताएँ

- पर्याप्त एन्क्रिप्शन और सुरक्षा उपायों के बिना सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण में वृद्धि से नागरिक डेटा के उल्लंघन का खतरा बढ़ जाता है।

4. सीमित क्षमता और कुशल जनशक्ति

- अपर्याप्त साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षित कार्मिक तथा विलंबित जांच त्वरित प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं।

5. डार्क वेब और मोबाइल ऐप्स के जरिए शोषण

- ऋण ऐप्स और गुमनाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी और शोषण के बढ़ते मामले।

साइबर लचीलापन मजबूत करने की रणनीतियाँ

1. **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** साइबर अपराध जांच और डिजिटल स्वच्छता में पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
2. **जन जागरूकता अभियान:** डिजिटल इंडिया और साइबर सुरक्षित भारत जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करके स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में डिजिटल साक्षरता अभियान।
3. **साइबर पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** फोरेंसिक और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के साथ हर जिले में साइबर अपराध इकाइयां स्थापित करना।
4. **नियामक ढांचा और सहयोग:** राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति के अनुरूप राज्य साइबर नीति विकसित करना; निजी साइबर सुरक्षा फर्मों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना।

उत्तर प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा, डिजिटल प्रणालियों में विश्वास सुनिश्चित करने और राज्य के विकास को समर्थन देने के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है।

Chronicle ias

प्रश्न.19 उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें। सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार सुधार कर सकती है।

उत्तर- भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश हाल ही में हुए सुधारों के बावजूद स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य तीन-स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली संचालित करता है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा - आधारभूत स्तर - असमान वितरण, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और अपर्याप्त सुविधाओं से ग्रस्त है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

सीएजी रिपोर्ट (2023) के अनुसार, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और उप-केंद्रों में आवश्यक चिकित्सा स्टाफ, उपकरण और बिजली की कमी है, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहल

1. आपातकालीन परिवहन सेवाएँ

- **102 एम्बुलेंस सेवा:**
  - गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और माताओं के लिए 24 × 7 निःशुल्क आपातकालीन परिवहन प्रदान करता है।
  - संस्थागत प्रसव तक पहुंच को बढ़ाता है तथा मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करता है।

2. डायग्नोस्टिक सुविधाओं का विस्तार

- **सभी जिलों में डायलिसिस सेवाएं:**
  - विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों में किफायती एवं सुलभ गुर्दे की देखभाल सुनिश्चित करना।
  - क्रोनिक किडनी रोग के रोगियों के लिए जेब से होने वाले खर्च को कम करता है।
- **74 जिलों में सीटी स्कैन सेवाएं:**
  - अब सस्ती सीटी स्कैन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे शीघ्र निदान और समय पर उपचार संभव हो सकेगा।
  - महंगी निजी सुविधाओं पर मरीज की निर्भरता कम हो जाती है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

3. **डिजिटल स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण**

- **सहायक कर्मचारियों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण :**
  - इसका उद्देश्य रोगी के साथ बातचीत और संतुष्टि में सुधार करना है।
  - सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में जनता का विश्वास बढ़ता है।
- **ई-कवच प्लेटफॉर्म :**
  - उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं और नवजात शिशुओं पर नजर रखने के लिए एक डिजिटल उपकरण।
  - प्रभावी निगरानी, बेहतर डेटा प्रबंधन और समय पर हस्तक्षेप का समर्थन करता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को और मजबूत करने के लिए सरकार को निम्नलि*त कार्य करने होंगे:

1. **बुनियादी ढांचे में निवेश करना:** आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं के साथ मौजूदा पीएचसी को उन्नत करें, कम सुविधा वाले क्षेत्रों में नए केंद्र स्थापित करें।
2. **मानव संसाधन को मजबूत करना :** स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भर्ती करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, तथा निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं :** कुशल प्रबंधन के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करें और स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों को लागू करें।
4. **सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना :** बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों के साथ आशा कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर जागरूकता अभियान चलाना।
5. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देना :** सेवाओं को पूरक बनाने और संसाधन जुटाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट्स के साथ सहयोग करना।

निष्कर्षतः, यद्यपि उत्तर प्रदेश ने सराहनीय कदम उठाए हैं, तथापि राज्य भर में सार्वभौमिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और जन-केंद्रित दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

प्रश्न.20 बुनियादी ढांचे, विरासत संरक्षण, रोजगार और टिकाऊ पर्यटन पर इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूपी पर्यटन नीति 2022 का मूल्यांकन करें।

उत्तर- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 का उद्देश्य बुनियादी ढांचे में वृद्धि, विरासत संरक्षण, रोजगार सृजन और टिकाऊ पर्यटन के माध्यम से राज्य को एक प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित करना है।

1. बुनियादी ढांचे का विकास

- **पूंजीगत सब्सिडी:** यह नीति होटल, कन्वेंशन सेंटर और वेलनेस रिसॉर्ट जैसे पर्यटन बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 40 करोड़ रुपये तक के प्रोत्साहन की पेशकश करती है।
- **पर्यटन क्षेत्र :** क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विंध्य धाम जैसे विशेष पर्यटन क्षेत्रों का विकास।
- **बेहतर कनेक्टिविटी:**
  - प्रमुख धार्मिक एवं विरासत स्थलों तक सड़क एवं रेल सम्पर्क बढ़ाया जाएगा।
  - अयोध्या और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक बेहतर पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **वायु परिवहन विस्तार:**
  - कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास से विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से धार्मिक और बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिला है।

2. विरासत संरक्षण

- **अनुकूली पुनः** उपयोग : विरासत संपत्तियों को उनके वास्तुशिल्पीय मूल्य को संरक्षित करते हुए पर्यटन उपयोग के लिए बढ़ावा देना।
- **उल्लेखनीय परियोजनाएँ:**
  - सांस्कृतिक पर्यटन को आकर्षित करने के लिए चुनार किले का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
  - आगंतुकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए लखनऊ और वाराणसी में हेरिटेज वॉक शुरू की गई।
- **सांस्कृतिक पुनरुत्थान:**
  - राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में दीपोत्सव और प्रयागराज में कुंभ मेले जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048

3. रोजगार सृजन

- **कौशल विकास :** पर्यटक गाइडों, आतिथ्य पेशेवरों और स्थानीय कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- **सामुदायिक समावेशन:**
  - ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए बुंदेलखंड में होमस्टे को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - स्थानीय शिल्प और संस्कृति आधारित पर्यटन में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सहायता।

4. टिकाऊ पर्यटन

- **इको-पर्यटन सर्किट:** सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व जैसे प्राकृतिक स्थलों के आसपास विकास।
- **हरित प्रथाएँ:** हरित भवन, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहन।
- **समुदाय-आधारित पर्यटन:** पर्यटन पहलों की योजना बनाने और उनसे लाभ उठाने में स्थानीय समुदायों को शामिल करने पर जोर।

संक्षेप में, यूपी पर्यटन नीति 2022 आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पारिस्थितिक जिम्मेदारी के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सफल कार्यान्वयन समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए यूपी को वैश्विक पर्यटन स्थल में बदल सकता है।

✓ Download the model answers of the test paper from www.chronicleias.in
✓ Watch the detailed video discussions of the questions in our website www.chronicleias.in
✓ For more details, call: 9953007636/9953007637 or WhatsApp: 9582219048